मेट्रो पॉलीटियन प्लान में 80 प्रतिशत मालवा क्षेत्र आरक्षित

- सभी गांव में बिना अनुमति नहीं होगा कोई निर्माण या विकास कार्य
- मुख्यालय इंदौर की बजाय उज्जैन में ....?

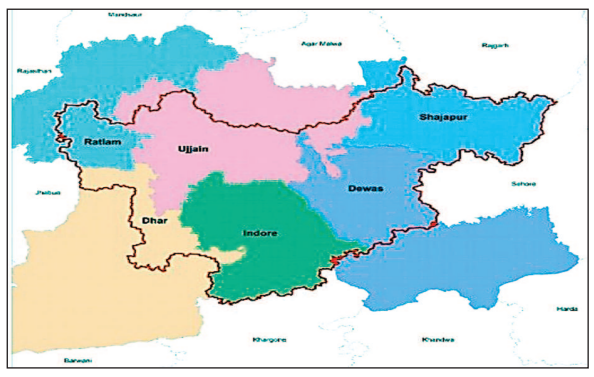

नव भारत न्यूज

इंदौर. सरकार ने उज्जैन इंदौर मेट्रो पॉलीटियन रीजन प्लान का 12 जून को गजट नोटिफिकेशन कर दिया है. इसमें छह जिले के 33 तहसील के 2781 गांव शामिल कर लिए गए हैं. इसका 16 हजार 88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होगा. खास बात यह है कि रीजन प्लान का मुख्यालय उज्जैन में होगा और केंद्र बिंदु इंदौर है प्लान में, यह अजीब बात दिखाई दे रही है. उक्त रीजन प्लान में शामिल 2781 गांव आरक्षित हो गए और सभी गांव में बिना अनुमति एक ईंट भी नहीं रखी जा सकेगी. यह बात अलग है कि उज्जैन इंदौर मेट्रो पॉलीटियन प्लान में 80 प्रतिशत मालवा क्षेत्र आरक्षित हो गया है.

उज्जैन-इंदौर मेट्रो पॉलीटियन प्लान पहले करीब 9 हजार वर्ग किलोमीटर का बनाया गया था, लेकिन बढ़ते बढ़ते 16 हजार 88 सौ वर्ग किलोमीटर का हो गया है. पहले चार जिले थे, लेकिन अब छह जिले इसमें शामिल हो गए हैं. आईडीए उक्त मेट्रो पॉलीटियन प्लान की नोडल एजेंसी है और मेहता एसोसिएट कंसल्टिंग एजेंसी है. मेट्रो पॉलीटियन प्लान का रिव्यू 16 हजार 88 वर्ग किलोमीटर में मालवा क्षेत्र की 33 तहसील के 2781 गांव जद में आ गए है. उक्त रीजन प्लान के लिए जमीन अधिग्रहण और क्षेत्र में निवेश क्षेत्र का आरक्षण होना बाकी है. उक्त रीजन प्लान में मालवा क्षेत्र के इतनी बड़ी संख्या में गांव शामिल करने से गांवों में सरकार की विभिन्न अनुमतियों के बिना कोई निर्माण कार्य नहीं किए जा सकेंगे. मुख्यालय इंदौर के बजाय उज्जैन करने से औद्योगिक केंद्र बिंदु इंदौर के अस्तित्व पर सवाल खड़े होने लाज़िमी है. यह बात अलग है कि अभी सिर्फ प्लान का क्षेत्र तय किया गया है, लेकिन निवेश और विकास का आरक्षण होना बाकी है. वही सबसे अहम कड़ी है, इस रीजन प्लान की.

9 से बढ़ाकर 16088 हजार वर्ग किलोमीटर पहुंचा प्लान

उज्जैन-इंदौर मेट्रो पॉलीटियन प्लान में करीब 9 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल किया गया था. इसमें पांच जिलों के 1756 गांव, 33 तहसील और 22 नगर पालिका और परिषद शामिल है. अब 2781 गांव और करीब 35 से ज्यादा नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हो गई है. उक्त प्लान में इंदौर का 3901.6, उज्जैन 2740.0, देवास 2086.0, धार 574 और शाजापुर का 33.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया है. इस प्रकार इंदौर मेट्रो पॉलीटियन प्लान 9336 .6 वर्ग किलोमीटर एरिया में था. अब रतलाम और शाजापुर की करीब 10 तहसील और शामिल की गई है. कुल 16,088 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल हो गया है.

पहले चार जिले, अब छह जिले

मेट्रो पॉलीटियन प्लान में पहले इंदौर, उज्जैन, धार और देवास ही शामिल थे, लेकिन अब रतलाम और शाजापुर जिले भी शामिल है. इस तरह 9 हजार वर्ग किलोमीटर से 16088 वर्ग किलोमीटर का हो गया इंदौर उज्जैन मेट्रो पॉलीटियन प्लान का क्षेत्रफल.

मानसून की चाल धीमी

23 तक दस्तक के आसार

34 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी

1 से 16 जून के बीच प्रदेश में 35% कम बारिश दर्ज की गई

भोपाल, 17 जून. मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री फिलहाल टल गई है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून अभी तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में ठहरा हुआ है, जिससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में इसकी प्रगति धीमी पड़ गई है. अब प्रदेश में मानसून के 21 से 23 जून के बीच पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

मानसून में हो रही देरी का असर कृषि गतिविधियों पर भी दिखने लगा है और खरीफ फसलों की बोवनी का इंतजार कर रहे किसानों की निगाहें बारिश पर टिकी हैं. बुधवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर और नीमच सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, रीवा, सतना, शहडोल, धार और बड़वानी सहित कुछ क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने और गर्मी का असर बने रहने के संकेत हैं. बीते पिछले 24 घण्टे में प्रदेश के कई हिस्सों में प्री-मानसूनी गतिविधियां जारी रहीं.

मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में सामान्यतः मानसून 15 जून तक प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस वर्ष इसकी रफ्तार धीमी है. 1 से 16 जून के बीच प्रदेश में सामान्य से लगभग 35 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, रतलाम और विदिशा सहित कई जिलों में वर्षा का आंकड़ा सामान्य से काफी नीचे है.

'पप्पू' और 'चप्पू' सब एक लाइन में

- महिदपुर के कार्यक्रम में सीएम ने कसा तंज
- अपने कर्मों की सजा भुगत रही कांग्रेस

नवभारत न्यूज़

इंदौर,17 जून. महिदपुर में लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे. उन्होंने मीनाक्षी नटराजन वाले मामले में कांग्रेसियों पर ही तंज कसा.

सीएम ने मंच से कहा कि कांग्रेसी सुन लें कान खोलकर, तुमने तो एक कौड़ी नहीं दी बहनों के लिए. लाड़ली बहनों के खाते में पैसे जाते हैं तो कांग्रेसी कहते हैं कि बहने इस रुपए से दारु पी जाती हैं. अरे डूब मरो कांग्रेसियों तुम्हारा चरित्र ऐसा है. कांग्रेस इसलिए अपने कर्मों की सजा भुगत रही है.

वो पप्पू और पप्पू को चलाने वाले चप्पू सब एक लाइन में है. सीएम ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन वाले मामले में नाम लिए बगैर कहा कि नौसिखिए को पार्टी की कमान आपने हाथ में दी है. अब वो गाड़ी आगे चलाने के बजाये पीछे ठोके तो हम भी क्या जानें. वो अपने कर्मों की जानें. सीएम ने कहा कि आने वाले समय में दुनिया महिदपुर के डोंगला से अपनी घड़ी का स्टेंडर्ड टाइम तय करेगी.

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 19 करोड़ रुपए से अधिक लागत के अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया. इनमें उच्च शिक्षा विभाग के 4.35 करोड़ रुपए लागत के महाविद्यालय भवन, लोक शिक्षण विभाग के तहत सेमलिया, महिदपुर रोड और कुंडीखेड़ा में कन्या स्कूल भवन, मोचीखेड़ा में 33/11 केवी उपकेंद्र तथा झारड़ा क्षेत्र के 13 उप स्वास्थ्य केंद्र भवन शामिल हैं. कुल मिलाकर लगभग 207 करोड़ रुपए के विकास कार्य जनता को समर्पित किए गए. सामाकोटा बैराज परियोजना से कई गांवों के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा.

लूट का खुलासा, 3 गिरफ्तार

विशेष संवाददाता

भोपाल, 17 जून. संगठित अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 29 लाख 65 हजार रुपये की लूट के मामले का त्वरित खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपियों के कब्जे से लूटी गई राशि में से 22 लाख 60 हजार रुपये नकद, लूट की रकम से खरीदी गई एक आई-20 कार तथा अन्य सामग्री बरामद की गई है. यह वारदात 11 जून को हुई थी, जब स्क्रैप व्यवसाय से जुड़े कर्मचारी मुकुल अग्रवाल विभिन्न प्रतिष्ठानों से भुगतान राशि एकत्र कर नकदी लेकर जा रहे थे. इसी दौरान जाइसवाल धर्मशाला के पास दो अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोककर मारपीट की और नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में आठ विशेष टीमों का गठन किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने 800 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया तथा तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से फर्जी नंबर प्लेट लगी एक संदिग्ध स्कूटर की पहचान की. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया था. वे पहले से मुकुल अग्रवाल की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और भुगतान संग्रहण के पहले स्थान से ही उनका पीछा कर रहे थे.

त्रिवेणी हिल्स पर फोरलेन पुल, खोलेगा सिंहस्थ के नए रास्ते

- आध्यात्मिक प्रवेश द्वार बनेगा आत्मलिंगेश्वर धाम
- इंदौर से आने वालों मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी
- सड़क बनाकर तैयार,ब्रिज का इंतजार

नवभारत न्यूज

उज्जैन. इंदौर से महाकाल की नगरी पहुंचने वाले अधिकांश श्रद्धालुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बनने जा रहा है, त्रिवेणी हिल्स कॉलोनी के पीछे शिप्रा नदी के ऊपर ब्रिज का निर्माण हो रहा है. ये मार्ग ग्राम सिकंदरी होता हुआ सिंहस्थ बायपास मार्ग से कनेक्ट होगा.

इस प्रस्तावित फोरलेन पुल और संपर्क मार्ग की लागत लगभग 24.81 करोड़ रुपये है. इंदौर रोड डी मार्ट और अंजू श्री होटल के सामने से त्रिवेणी हिल्स कॉलोनी से होती हुई फोरलेन सड़क बनाकर तैयार है. इसके आगे पुल का निर्माण चल रहा है.

शहर के भीतर भीड़ से मुक्ति - 50 करोड़ श्रद्धालुओं, साधु-संतों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव चाहते है कि देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु इंदौर की तरफ से ही प्रतिदिन आएंगे, ऐसे में शहर में क्राउड ना बढ़े और सीधे यात्री मेला क्षेत्र में पहुंच सके इसलिए यह मार्ग सुलभ होगा. श्रद्धालुओं को शहर के भीतरी हिस्सों के भारी यातायात से गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे सीधे मेला क्षेत्र, पड़ाव क्षेत्र, घाटों और धार्मिक स्थलों तक पहुंच सकेंगे.

आत्मलिंगेश्वर धाम नया केंद्र-जहां पुल बन रहा है उसके समीप आत्मलिंगेश्वर महादेव मंदिर आने वाले वर्षों में एक बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है. शिप्रा तट के समीप स्थित यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक वातावरण और सेवा गतिविधियों के कारण पहले से ही श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मंदिर परिसर के आसपास यज्ञशाला, धर्मशाला, गौशाला और अन्य धार्मिक सुविधाओं के विस्तार की तैयारियां चल रही हैं. यहां स्थित प्रसिद्ध बस का बगीचा वर्षों से धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रहा है. सिंहस्थ-2028 में इस पूरे क्षेत्र को और विकसित कर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.

सेवा, भंडारे और संत परंपरा का संगम

नवभारत से चर्चा में शशांक गोरे और लक्की गुरु ने बताया कि क्षेत्र में वर्षों से नि:स्वार्थ सेवा का कार्य किया जा रहा है. बम भोला द्वारा स्थापित कुटिया का लगातार विस्तार किया जा रहा है और बड़ी संख्या में सेवक यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहते हैं. उन्होंने बताया कि सिंहस्थ-2028 के दौरान यहां विशाल भंडारे, लंगर और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाएगी. देश-विदेश से आने वाले साधु-संतों और श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान विश्राम, दर्शन और आध्यात्मिक अनुभूति का प्रमुख केंद्र बनेगा. महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं और भविष्य में यह संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है.

आईएएस अधिकारियों के थोकबंद तबादले

भोपाल, 17 जून. सरकार ने बुधवार देर शाम 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए. इसमें अनिरुद्ध मुकर्जी को मौजूदा दायित्वों के साथ अपर मुख्य सचिव पर्यावरण विभाग व पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक एप्को का प्रभार अतिरिक्त रूप से दिया गया है. वहीं के सी गुप्ता अपर मुख्य सचिव को मौजूदा दायित्वों के साथ कृषि उत्पादन आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.

यहां बता दें कि 9 जून को सिया के चेयरमेन शिवनारायण सिंह चौहान ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बर्णवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. इधर भोपाल संभाग आयुक्त संजीव सिंह का भी हटना तय माना जा रहा था, लिहाजा इस प्रशासनिक सर्जरी में उनको अब नई जिम्मेदारी दे दी गई है. इधर कलेक्टरी के दौरान छिंदवाड़ा जिले में अपने नवाचार को लेकर पहचान बनाने वाले शीलेन्द्र सिंह को रीवा संभाग के कमिश्नर की बड़ी जिम्मेदारी देकर उनके नवाचार को एक तरह से सरकार ने सम्मान दिया है. पिछले दिनों आईएएस अफसरों के सोशल मीडिया ग्रुप में शीलेन्द्र सिंह चर्चा का विषय बने हुए थे. दरअसल छिंदवाड़ा जिले में उनके नवाचार को लेकर जिक्र आने पर आईएएस अफसरों ने उन्हें ग्रुप में बधाई देना शुरू कर दिया था, लेकिन तब ही अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग दीपाली रस्तोगी ने इसका श्रेय सीधी भर्ती वाले आईएएस को भी देने की कोशिश की, जिससे विवाद की स्थिति बन गई थी. इस विवाद ने सीधी भर्ती और एसएएस से आईएएस बनने वाले अफसरों के बीच एक रेखा खींच दी थी, लेकिन लगता है कि सरकार ने शीलेन्द्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देकर श्रेय छिनने की कोशिश करने वाले अफसरों को कड़ा जवाब दे दिया है. इधर मंत्री राकेश सिंह से विवाद करना अपर आयुक्त अरविंद कुमार शाह को भारी पड़ा है, उन्हें भी हटा दिया गया है.

बामरा को अतिरिक्त प्रभार

गुलशन बामरा प्रमुख सचिव को मौजूदा दायित्वों के साथ पीएस अनुसूचित जाति कल्याणप विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है, इसी तरह सुश्री सोनिया मीना अपर सचिव को वर्तमान दायित्वों के साथ आयुक्त सह संचालक संस्थागत वित्त का प्रभार अतिरिक्त रूप से दिया गया है. मुकेश चंद्र गुप्ता द्वारा नया कार्यभार ग्रहण करने पर मनीष सिंह सचिव केवल जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

अधिकारी -	वर्तमान पदस्थापना -	नई पदस्थापना
मुकेश चंद्र गुप्ता-	सचिव मप्र मानव अधिकार आयोग-	पीएस जेल विभाग
डॉ. ई .रमेश कुमार-	पीएस अजाक विभाग -	पीएस राजस्व विभाग
विवेक कुमार पोरवाल-	पीएस राजस्व विभाग-	पीएस खनिज साधन विभाग
संजीव सिंह -	आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल -	सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग
बाबू सिंह जामोद -	आयुक्त रीवा संभाग रीवा -	सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग
दीपक सिंह -	ओएसडी सह सचिव राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल -	आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं
आलोक कुमार सिंह-	सचिव सीएम, खनिज साधन विभाग अति .प्रभार -	पंजीयन आईजी व अधीक्षक मुद्रांक भोपाल
अमित तोमर -	पंजीयन आईजी व अधीक्षक मुद्रांक मप्र भोपाल -	एमडी ऊर्जा विकास निगम, आयुक्त नवीन, नवकरणीय ऊर्जा, अतिरिक्त प्रभार
सत्येन्द्र सिंह -	ओएसडी सह संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं-	आयुक्त सह संचालक ओबीसी व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
कर्मवीर शर्मा -	आयुक्त सह संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण -	आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल
भास्कर लक्षकार -	आयुक्त कोष एवं लेखा मप्र भोपाल -	आयुक्त सह संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण
दिनेश श्रीवास्तव -	ओएसडी सह संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण -	ओएसडी सह सचिव मप्र राज्य निर्वाचन आयोग
शीलेन्द्र सिंह -	सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग-	आयुक्त रीवा संभाग रीवा
सौरभ कुमार सुमन -	ओएसडी सह आयुक्त सह संचालक ओबीसी व अल्पसंख्यक कल्याण-	ओएसडी सह आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण
नेहा मारव्या सिंह -	अपर सचिव जनजातीय कार्य विभाग -	संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं
मनोज पुष्प-	ओएसडी सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं -	संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
प्रीति जैन -	संभागीय सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल इंदौर -	संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय इंदौर
रोहित सिंह-	अपर सचिव वित्त विभाग -	एमडी मप्र पाठ्यपुस्तक निगम
हर्षिका सिंह-	सीईओ मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन -	संचालक बजट मप्र भोपाल
भारती ओगरे जाटव -	अपर सचिव खनिज साधन विभाग-	अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग
अमनबीर सिंह बैंस-	एमडी ऊर्जा विकास निगम भोपाल -	ओएसडी सह आयुक्त कोष एवं लेखा
कैलाश वानखेड़े -	अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास -	अपर सचिव ऊर्जा विभाग
अमर बहादुर सिंह-	अपर आयुक्त राजस्व जबलपुर संभाग -	अपर सचिव जनजातीय कार्य विभाग
पवन कुमार जैन -	अपर आयुक्त राजस्व सागर संभाग -	उप सचिव सहकारिता विभाग
रानी बाटड -	उप सचिव सहकारिता विभाग -	उप सचिव श्रम विभाग
विनय निगम-	जीएम मप्र पाठ्य पुस्तक निगम -	सीईओ मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल
मंजूषा विक्रांत राय-	उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग -	उप सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग
शैली कनाष-	संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय इंदौर -	संभागीय सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल इंदौर
अरविंद कुमार शाह-	अपर आयुक्त नगर पालिक निगम जबलपुर -	सीईओ आयुष्मान भारत भोपाल

राजगढ़ में वैक्सीन सुरक्षा पर उठे सवाल

जीतू पटवारी ने जताई चिंता

विशेष संवाददाता

भोपाल, 17 जून. राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 30 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने के बाद टीकाकरण के लिए सुरक्षित रखी गई महत्वपूर्ण वैक्सीनों के खराब होने के आरोपों ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं.

इस मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है. विवाद उस समय और गहरा गया जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के परस्पर विरोधी बयान सामने आए. बताया जा रहा है कि स्थानीय ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने वैक्सीनों के प्रभावित होने की आशंका जताई है, जबकि जिला टीकाकरण अधिकारी ने सभी वैक्सीनों को सुरक्षित बताया है. इन विरोधाभासी दावों ने स्वास्थ्य विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में व्याप्त व्यापक संकट का संकेत बताया.

कोल्ड-चेन बैकअप प्रणाली क्यों उपलब्ध नहीं

पटवारी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों की कमियों का समाधान निजीकरण नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना है. उन्होंने सवाल उठाया कि लंबे समय तक बिजली बाधित रहने के बावजूद वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था और कोल्ड-चेन बैकअप प्रणाली क्यों उपलब्ध नहीं थी. कांग्रेस ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय और समयबद्ध जांच, जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

हमले में घायल युवक की मौत

04 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

भिण्ड 17 जून. शहर के गौरी तालाब क्षेत्र में 11 दिन पहले हुए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल एक युवक की बुधवार को उपचार के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के खिरिका मोतीपुरा निवासी सचिन राजावत पर गत छह जून की दोपहर गौरी तालाब क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया था. आरोप है कि कुछ लोगों ने पहले उसके साथ मारपीट की और बाद में उसे विक्रमपुरा स्थित एक मकान पर ले जाकर पाइप, सरिया, डंडों और लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा. हमले में सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया था. परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भिण्ड लेकर पहुंचे जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई. हालांकि उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और लगातार तबीयत बिगड़ती रही.

परिजनों के मुताबिक मारपीट में आई अंदरूनी चोटों के कारण सचिन को लगातार दर्द और अन्य परेशानियां बनी हुई थीं. हालत गंभीर होने पर 15 जून को उसे बेहतर उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया. वहां उसे गजानन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उपचार के दौरान आज उसकी मौत हो गई.

पेंशनर शिविर में सुनी गईं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याएं

भोपाल. सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना (सडिपुका) निशातपुरा में मुख्य कारखाना प्रबंधक प्रफुल्ल वी. कोहाडे के मार्गदर्शन में पेंशनर शिविर का आयोजन किया गया. प्रशासनिक भवन सभागार में आयोजित बैठक में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों और रेल प्रशासन के बीच संवाद हुआ.

शिविर में पेंशन संशोधन, पारिवारिक पेंशन, चिकित्सा सुविधाओं और लंबित प्रकरणों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन एवं पेंशनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पेंशनरों की समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं.

हमला | दिग्विजय सिंह ने दोहराई जवाबदेही की मांग

आरएसएस की पारदर्शिता पर उठे सवाल

विशेष संवाददाता

भोपाल, 17 जून. वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की कानूनी स्थिति, वित्तीय स्त्रोतों और सार्वजनिक जवाबदेही को लेकर एक बार फिर पारदर्शिता की मांग उठाई है.

उन्होंने कहा कि वर्षों से उठाए जा रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है. दिग्विजय सिंह की यह प्रतिक्रिया कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे द्वारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखे गए उस पत्र के बाद आई है, जिसमें संगठन की कानूनी स्थिति, वित्तीय पारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन संबंधी जानकारी मांगी गई है. सिंह ने कहा कि खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे वही हैं जिन्हें वह पहले भी कई बार सार्वजनिक रूप से उठा चुके हैं. उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर 2021 को उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक विस्तृत पत्र लिखकर आरएसएस की पंजीकरण स्थिति, वित्तीय लेन-देन, कर अनुपालन और संगठनात्मक जवाबदेही की जांच कराने की मांग की थी. उनका तर्क था कि यदि ट्रस्ट, धर्मार्थ संस्थाएं, सोसायटी, कंपनियां और राजनीतिक दल वित्तीय खुलासे तथा कानूनी अनुपालन के दायरे में आते हैं, तो व्यापक संगठनात्मक नेटवर्क और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक गतिविधियों वाले आरएसएस पर भी समान मानदंड लागू होने चाहिए.

नागपुर के आरटीआई कार्यकर्ता मोहनिश जबलपुरे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का हवाला देते हुए सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान आरएसएस द्वारा कथित रूप से सात करोड़ से अधिक खाद्य पैकेट और एक करोड़ राशन किट वितरित किए गए थे. उन्होंने इतने बड़े स्तर पर संचालित गतिविधियों के लिए धन के स्रोतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है. दिग्विजय सिंह ने यह भी याद दिलाया कि नवंबर 2025 में उन्होंने सीधे मोहन भागवत को पत्र लिखकर आरएसएस की अपंजीकृत स्थिति की तुलना हिंदू धर्म से किए जाने पर आपत्ति जताई थी.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60